

लोकतंत्र में राज्यपाल की भूमिका की पुनर्कल्पना

यह एडिटरियल 13/01/2025 को द हद्वि में प्रकाशित “[Willful violation: On the Tamil Nadu Governor's conduct](#)” पर आधारित है। इस लेख में तमिलनाडु के राज्यपाल की सर्वोच्च न्यायालय की जाँच पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें राज्य के वधियकों को मंजूरी न देने में राज्यपाल के अतिक्रमण पर चर्चा व्यक्त की गई है। यह संकट भारत के संघीय कार्यद्वैच में राज्यपाल की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

प्रलिस के लिये:

[राज्यपाल](#), [सर्वोच्च न्यायालय](#), [राष्ट्रपति](#), [राष्ट्रपति शासन](#), [राज्य लोक सेवा आयोग](#), [महाधिवक्ता](#), [स्वायत्त ज़िले](#), [एस.आर. बोममई नरिणय](#), [अनुच्छेद 361](#), [सरकारिया आयोग](#), [पुंछी आयोग \(2010\)](#)

मेन्स के लिये:

भारत में राज्यपाल के प्रमुख संवैधानिक कार्य, भारत में राज्यपाल के कार्यालय से संबंधित प्रमुख चर्चाएँ।

तमिलनाडु के [राज्यपाल](#) की हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) द्वारा की गई जाँच से राज्यपालों के कार्यालयों द्वारा संवैधानिक अतिक्रमण के बढ़ते पैटर्न पर प्रकाश पड़ता है। यह मामला [राज्यपाल द्वारा वधियकों को मंजूरी न देने](#) और उन्हें [राष्ट्रपति](#) के पास भेजने पर आधारित है, जबकि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य वधियनसभा द्वारा दूसरी बार पारित किये जाने के बाद ही वधियक को मंजूरी दी जानी चाहिये। राज्य वधियनमंडल में लंबे समय तक [वल्लिब और कथति अवरोध](#) ने [राज्यपाल की शक्तियों के दुरुपयोग](#) के बारे में चर्चाओं को बढ़ा दिया है। जबकि अटॉर्नी-जनरल केंद्रीय कानूनों के साथ टकराव का हवाला देते हैं, मुख्य मुद्दा [राज्य शासन में राज्यपाल की भागीदारी](#) है। यह संकट [भारत के संघीय कार्यद्वैच में राज्यपालों की भूमिका और अधिकार का पुनर्मूल्यांकन](#) करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

भारत में राज्यपाल के प्रमुख संवैधानिक कार्य क्या हैं?

- **राज्य का कार्यकारी प्रमुख:** राज्यपाल राज्य के मुख्य कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करता है, जो नाममात्र प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है, जबकि विह केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है।
 - [अनुच्छेद 154](#) के अनुसार, राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयाँ राज्यपाल के नाम से की जाती हैं और [अनुच्छेद 166](#) के तहत, कार्य संचालन के नियम राज्यपाल द्वारा बनाए जाते हैं।
 - इसके अतिरिक्त, राज्यपाल [मुख्यमंत्री](#) और उनकी सलाह पर मंत्रपरिषद की नियुक्ति करता है।
- **वधियी भूमिका और वधियकों पर स्वीकृति:** राज्य वधियनमंडल और संघ के बीच संवैधानिक कड़ी के रूप में, संवैधानिक [अनुच्छेद 174](#) के तहत राज्यपाल [राज्य के वधियनमंडल का सत्र आमंत्रित, सत्रावसान और उसका वधितन](#) करता है।
 - किसी वधियक को कानून बनने के लिये [राज्यपाल की स्वीकृति](#) प्राप्त होनी चाहिये, जैसा कि संघ सत्र पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है अथवा इसे [अनुच्छेद 200](#) के तहत राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षणित रखा जा सकता है।
 - राज्य के वधिय शासन में राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि [अनुच्छेद 207](#) के तहत उनकी सफारिश के बिना [वधियनसभा में कोई भी धन वधियक पेश नहीं](#) किया जा सकता है।
 - वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि [राज्य का वधित संवैधानिक और राजकोषीय जम्मेदारियों के अनुरूप](#) हो।
- **त्रिशंकु वधियनसभाओं में वधिकाधीन शक्तियाँ और भूमिका:** राज्यपाल कुछ स्थितियों में वधिकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जैसे [अनुच्छेद 356](#) के तहत [राष्ट्रपति शासन](#) की सफारिश करना या त्रिशंकु वधियनसभा के मामले में किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित करना।
 - वे [उन मामलों पर भी नरिणय](#) लेते हैं जहाँ संवैधानिक उन्हें [मंत्रपरिषद की सलाह से स्वतंत्र होकर वधिकाधिकार](#) प्रदान करता है।
- **नियुक्तियों और प्रशासन में भूमिका:** राज्यपाल [अनुच्छेद 165 और 316](#) के तहत [महाधिवक्ता](#) और [राज्य लोक सेवा आयोग](#) के सदस्यों सहित प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है।
 - वे [राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति](#) करते हैं, जो हाल के वर्षों में एक विवादास्पद मुद्दा रहा है।
 - यह कार्य राज्य के सुचारु प्रशासन को सुनिश्चित करता है, लेकिन इसे राज्य सरकार के परामर्श से किया जाना चाहिये।
- **राष्ट्रपति शासन लागू करने में भूमिका:** [अनुच्छेद 356](#) के तहत, यदि राज्यपाल का मानना है कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो वे राष्ट्रपति शासन की सफारिश कर सकते हैं।
 - यह [प्रावधान आपातकालीन उपाय के रूप में](#) है, लेकिन इसका प्रायः राजनीतिक लाभ के लिये दुरुपयोग किया जाता है।

?????? ???? ????:

प्रश्न. “भारत में राज्यपाल का कार्यालय प्रायः संघवाद और संवैधानिक औचित्य पर बहस के केंद्र में रहा है।” राज्यपाल की भूमिका से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा कीजिये तथा नषिपक्षता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये सुधार सुझाइये। (250 शब्द)

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????

प्रश्न 1. नमिनलखिति में से कौन-सी कसी राज्य के राज्यपाल को दी गई वविकाधीन शक्तियाँ हैं? (2014)

1. भारत के राष्ट्रपतको, राष्ट्रपतशासन अधरौपति करने के लयि रपिर्ट भेजना
2. मंत्रियों की नयुक्तकरना
3. राज्य वधिानमण्डल द्वारा पारति कतपिय वधियकों को, भारत के राष्ट्रपतके वचार के लयि आरक्षति करना
4. राज्य सरकार के कार्य संचालन के लयि नयिम बनाना

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

??????

प्रश्न 1. क्या उच्चतम न्यायालय का नरिणय (जुलाई 2018) दल्लि के उप-राज्यपाल और नरिवाचति सरकार के बीच राजनैतिक कशमकश को नपिटा सकता है? परीक्षण कीजयि। (2018)

प्रश्न 2. राज्यपाल द्वारा वधियाी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का वविचन कीजयि। वधियािका के समक्ष रखे बना राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनः प्रख्यापन की वैधता की वविचना कीजयि। (2022)